संतुलन बहाल करना

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

लेखक -हर्ष वी. पंत (प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज, लंदन)

19 दिसंबर, 2018

"मालदीव में लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत बनाने के लिए भारत को निवेश करना चाहिए।"

ऐसा लगता है कि इस हफ्ते मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की भारत की तीन दिवसीय यात्रा भारत-मालदीव संबंधों के खराब दौर को समाप्त करने में काफी सहायक सिद्ध होगी। यह 400,000 लोगों वाले एक हिंद महासागरीय राष्ट्र के राष्ट्रपति बनने के बाद श्री सोलिह की पहली विदेश यात्रा है। सितंबर माह में मालदीव में हुए राष्ट्रपति चुनाव में आश्चर्यचकित रूप से उन्होंने अब्दुल्ला यमीन को हराया और तब से, उन्होंने भारत के साथ अपने देश के संबंधों को दोबारा बेहतर बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। गौरतलब हो कि इससे पहले यमीन ने मालदीव का रुख चीन की ओर मोड़ दिया था और श्री सोलिह की जीत ने उनलोगों के मंसूबों पर पानी फेर दिया जो मालदीव में लोकतांत्रिक ताकतों को कमजोर करने के पक्ष में थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर में मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में श्री सोलिह के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया था, जो मोदी की पहली और 2011 के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में पहली यात्रा थी। देखा जाये तो श्री मोदी ने 2014 में भारत में हुए चुनाव के बाद भारत के सभी पड़ोसियों को बुलावा भेजा था, लेकिन वे श्री यमीन को शामिल करने के लिए अनिच्छुक दिखे।

मार्च, 2015 में मालदीव की उनकी योजनाबद्ध यात्रा को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि राजनीतिक माहौल श्री यमीन के शासन के अंतर्गत बिगड़ चुका था। श्री सोलिह की जीत के एक मजबूत समर्थन में, श्री मोदी ने बताया कि मालदीव में हुए हालिया चुनाव ने लोकतंत्र, कानून, शासन और समृद्ध भविष्य के लिए लोगों की सामूहिक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत मालदीव को एक स्थिर, लोकतांत्रिक, समृद्ध और शांतिपूर्ण गणराज्य बनते देखना चाहता है।

इस संबंध के कारक

श्री सोलिह की भारत यात्रा ने दोनों पक्षों को अपने परंपरागत रूप से घनिष्ठ संबंधों को और बेहतर बनाने पर जोर दिया है। श्री सोलिह ने भारत का मालदीव को निकटतम मित्र कहा और भारत सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए अपनी सरकार की भारत-प्रथम नीति की भी पुष्टि की। भारत ने अपने हिस्से के रूप में मालदीव के लिए बजटीय समर्थन, मुद्रा स्वैप समझौते और क्रेडिट के रूप में 1.4 बिलियन डॉलर का वित्तीय सहायता पैकेज घोषित किया है। दोनों इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सहमत हुए हैं कि वे अन्य महासागर क्षेत्र (आईओआर) में सहयोग को मजबूत करेंगे और एक दूसरे के सुरक्षा हितों को हमेशा ध्यान में रखेंगे।

वे समेकित गश्ती और हवाई निगरानी के माध्यम से आईओआर में समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए सहमत हुए हैं। व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के प्रयास में, श्री मोदी ने मालदीव में निवेश करने के लिए भारतीय कंपनियों के विस्तार का स्वागत किया है। इसके अलावा, दोनों देशों ने इस बात की भी पुष्टि की है कि वें मत्स्य विकास, पर्यटन, परिवहन, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और अक्षय ऊर्जा एवं संचार के संबंध में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर अधिक ध्यान देंगे।

चीनी कारक

देखा जाये तो नई दिल्ली के परिप्रेक्ष्य से यह काफी महत्वपूर्ण है कि श्री सोलिह मालदीव में सफल साबित हुए। ऐसा इसलिए क्योंकि श्री यमीन के शासन काल में मालदीव ने भारत को दरकिनार करते हुए चीन का चुनाव किया, प्रमुख बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के लिए चीनी निवेश का स्वागत किया और एक विवादास्पद मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर करते हुए भारत को स्पष्ट संकेत दिया कि भारत से अधिक उसके लिए चीन मायने रखता है। इसके अलावा, उस दौरान मालदीव ने राजनीतिक नियंत्रण और सुरक्षा संबंधों के संदर्भ में भारत द्वारा किये गये आग्रह को साफ तौर पर नजरअंदाज कर दिया था।

वर्तमान में मालदीव की अर्थव्यवस्था में चीन की भूमिका पर काफी ध्यान देने की आवश्यकता है जहाँ मालदीव द्वारा बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए चीन के कंस्ट्रक्शन कंपनियों से लिये गये उधार की चिंता व्याप्त है। इन बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में चीन-मालदीव मैत्री ब्रिज शामिल है, जो माले के पूर्वी किनारे को हुलहुले द्वीप के पश्चिमी कोने से जोड़ता है।

एक अनुमान के अनुसार मालदीव द्वारा चीन से लिया गया ऋण कम से कम 1.3 बिलियन डॉलर का है जो इस राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद का एक-चौथाई हिस्सा है। इस संकट के साथ, नई मालदीवियन सरकार अपने विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मद्द के रूप में भारत को बजटीय समर्थन के रूप में देख रही है और साथ ही चीन के साथ एफटीए को संशोधित करने की भी योजना बना रही है।

मोदी सरकार भी यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि मालदीव को सहायता समय पर पहुँचाया जाए ताकि नई दिल्ली मालदीव की विदेश नीति और राजनीति में अपनी खोई हुई जगह वापस ले सके। माले ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सोलिह सरकार के लिए मालदीव के पड़ोसी देशों की स्पष्ट रूप से प्राथमिकता होगी, जहाँ फिर से चीन आर्थिक साझेदार के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका

निभाने के लिए सबसे आगे रहेगा। इसलिए यह सोचना कि चीन मालदीवियन विदेश नीति से गायब हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा और भारत को भी ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन भौगोलिक रूप से देखे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मालदीव में राजनीतिक विकास के प्रक्षेपण को निर्धारित करने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

पिछले कुछ वर्षों में मालदीव संकट के संदर्भ में भारत का धैर्य काफी सराहनीय है। अन्य समान विचारधारा वाले क्षेत्रीय और अतिरिक्त क्षेत्रीय खिलाड़ियों के साथ अपनी प्रतिक्रिया को समन्वयित करके, भारत ने श्री यमीन को कई बार बताया कि मालदीव के लिए अभी भी भारत खड़ा हैं तो अब मालदीव को यह फैसला करना है कि इसे चीन से दूर जाना चाहिए या नहीं। उदाहरण के लिए, नवंबर में सिंगापुर में हुए क्वाड देशों की एक बैठक के बाद, अमेरिका ने नई मालदीवियन सरकार के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया था।

घरेलू गतिशीलता

वर्तमान में मालदीव को भारत के समर्थन की आवश्यकता होगी क्योंकि इसके समक्ष जो चुनौतियां है वो गंभीर हैं। श्री यमीन से संघर्ष ने देश के संस्थागत ढ़ांचे को तबाह कर दिया है, जिसमें इस्लामवादी चरमपंथ का खतरा भी शामिल है।

निश्चितरूप से श्री सोलिह के लिए शासन करना चुनौतीपूर्ण रहेगा क्योंकि श्री यमीन को हटाने के लिए एकजुट हुई सेनाएं देश को चलाने और अपनी लोकतांत्रिक नींव को मजबूत बनाने में पर्याप्त नहीं हैं। अंत में अधिक निवेश नई दिल्ली को अपने पड़ोस में लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत बनाने में मद्द करेगा और एक बेहतर नीति भारत को बेहतर रिटर्न प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा।

GS World टीम...

भारत-मालदीव संबंध

चर्चा में क्यों?

- मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह तीन दिवसीय भारत यात्रा पर हैं।
- भारत और मालदीव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हिंद महासागर में शांति व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है।
- इसके साथ ही भारत इस द्वीपीय देश को 1.4 अरब डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। यह सहायता राशि भारत द्वारा मालदीव को दी जाने वाली सबसे बड़ी राशि है।
- दोनों पक्षों ने संस्कृति सहयोग, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स सहयोग, कृषि व्यापार के लिए बेहतर वातावरण बनाने समेत चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

पृष्ठभूमि

- मालदीव के साथ भारत के सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं।
- मालदीव के साथ नई दिल्ली का धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक और व्यावसायिक संबंध है।
- वर्ष 1965 में आजादी के बाद मालदीव को सबसे पहले मान्यता देने वाले देशों में भारत शामिल था। बाद में भारत ने वर्ष 1972 में मालदीव में अपना दूतावास भी खोला।
- इब्राहिम सोलिह नवंबर, 2018 में मालदीव के राष्ट्रपति बने थे।
- पीएम नरेंद्र मोदी इब्राहिम सोलिह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह को कार्यभार संभालने के बाद उनकी पहली विदेशी यात्रा है।

समझौते से संबंधित मुख्य तथ्य

- भारत अगले पांच वर्षों में मालदीव के नागरिकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए अतिरिक्त 1000 सीटें देने का भी निर्णय किया है।
- दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भी भारत पूर्ण सहयोग देगा। बेहतर कनेक्टिविटी से वस्तु एवं सेवा, सूचना, विचारों, संस्कृति और लोगों के आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा।
- बातचीत के दौरान दोनों पक्ष हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर भी सहमत हुए।
- भारत और मालदीव ने समुद्री डकैती, आतंकवाद, संगठित अपराध, मादक पदार्थो और मानव तस्करी समेत सामान्य चिंताओं के विषय पर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।
- भारत ने दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढांचे, कृषि, क्षमता निर्माण और पर्यटन के क्षेत्र में भागादीरी को मजबूत करने का आह्वान किया।
- दोनों देश के नेताओं ने मत्स्य विभाग, पर्यटन, यातायात, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और संचार के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रमंडल में दोबारा शामिल होने के निर्णय की सराहना की और देश के हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में शामिल होने का स्वागत किया।

भारत-मालदीव सम्बन्ध

- भारत और मालदीव के संबंध सामरिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग में दोस्ताना और करीबी रहे हैं। भारत ने द्वीप राष्ट्र पर सुरक्षा बनाए रखने में योगदान दिया हैं।
- मालदीव अब कम विकसित देशों की श्रेणी से बाहर निकलकर एक मध्यम आय वाला देश बन गया है।
- भारत सरकार की ओर से मालदीव को दी जाने वाली सहायता की सराहना की और घर और अवसंरचना विकास में निजी क्षेत्र की संलिप्तता, जल व निकासी प्रणाली, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा व पर्यटन क्षेत्र समेत कई क्षेत्रों के विकास में सहयोग के लिए पहचान की।
- मालदीव हिंद महासागर में स्थित 1200 द्वीपों का देश है, जो भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से काफी अहम है। मालदीव के समुद्री रास्ते से निर्वाध रूप से चीन, जापान और भारत को एनर्जी की सप्लाई होती है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारत का मालदीव के साथ संबंध है-
   1. धार्मिक संबंध
   2. भाषाई संबंध
   3. सांस्कृतिक संबंध
   4. व्यावसायिक संबंध

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य नहीं है/हैं?

   (a) केवल 4 (b) 1 और 2
   (c) 1, 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. हाल ही में मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन हिंद महासागर में शांति व सुरक्षा को बनाए रखने हेतु सहयोग बढ़ाने के लिए तीन दिवसीय भारत यात्रा पर आए।
   2. हाल ही में भारत और मालदीव ने सांस्कृतिक सहयोग, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स सहयोग, कृषि व्यापार के लिए बेहतर वातावरण बनाने समेत चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य नहीं है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. हिंद महासागर में स्थित मालदीव 1200 द्वीपों का देश है।
   2. मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद सोलिह का कार्यभार संभालने के बाद भारत की उनकी पहली विदेश यात्रा है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य नहीं है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्नः 'पड़ोसी देशों के साथ संबंध भारत की विदेश नीति का केन्द्रीय तत्त्व रहा है।' हाल ही में मालदीव के साथ भारत के सुधरते संबंध ना सिर्फ भारत के लिए आर्थिक महत्त्व रखता है, अपितु सामरिक महत्त्व भी रखता है। चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

नोट : 18 दिसम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2 (c), 3 (b), 4 (d) होगा।